



UNIVERSAL PRIME ALUMINIUM LIMITED

Office : CENTURY BHAVAN, 771, Dr. ANNIE BESANT ROAD, WORLI, MUMBAI - 400 030.
Phone : 022 - 24307437 / 24304198 ★ E-mail : upalbby@gmail.com
CIN NO. : L28129MH1971PLC015207

July 4, 2020

To
Listing Department,
BSE Limited
PhirozeJeejeebhoy Tower,
Dalal Street,
Mumbai - 400 001

Security Code: 504673

Dear Sir/Madam,

Subject: Submission of Post Public Announcement in respect of proposed Delisting equity shares of Universal Prime Aluminium Limited:

With reference to the captioned subject please find attached the soft copy of the "Post Public Announcement" newspaper advertisement published on July 4, 2020 in Business Standard English edition and Hindi edition having nationwide circular and Mumbai Lakshadweep Marathi edition in respect of the proposed acquisition and voluntary delisting of the equity shares of face value of Rs. 10/- each ("Equity Shares") of the Company from the BSE Limited (hereinafter referred to as the "BSE"/ "Stock Exchange") pursuant to Regulation 18 and other applicable provisions of the Securities and Exchange Board of India (Delisting of Equity Shares) Regulations, 2009, as amended from time to time ("Delisting Regulations") ("Delisting Offer").

The Acquirer could not make the newspaper advertisement on 27th March, 2020 in terms of Regulation 18 and other applicable provisions as there was Country wide lock-down due to impact of CoVID - 19 pandemic from 22nd March, 2020, the Acquirer could not access their office till 08th June, 2020. Hence various events to be taken by the Acquirer/Promoter got delayed, which was major force, i.e. reason beyond the control of Acquirer/Promoter as the entire country was in lock down mode, there were restrictions on the physical movement of every individual in the country. Kindly condone the delay if any.

For Universal Prime Aluminium Limited

Nawal Kishor Bagri
Director

बड़ी हिस्सेदारी बिक्री पर नजर बनी रहेगी

दीपम सचिव का कहना है कि कोविड-19 महामारी की वजह से कुछ समस्याएं आई हैं

जश कृपलानी मुंबई, 3 जुलाई

निवेश एवं सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन (दीपम) के सचिव तुहिन कांत पांडे ने शुक्रवार को कहा कि भले ही कोविड-19 महामारी ने कुछ समस्याएं पैदा की हैं, लेकिन सरकार चालू वित्त वर्ष में अपने 2.1 लाख करोड़ रुपये के विनिवेश लक्ष्य को पूरा करने के लिए बड़ी हिस्सेदारी बिक्री पर ध्यान बरकरार रखेगी।

भारत बॉन्ड ईटीएफ पर एक वेबिनार में बोलते हुए पांडे ने कहा, 'कई रणनीतिक सौदे हो रहे हैं और वे सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। कोविड-19 महामारी की वजह से कुछ समस्या आई थी।'

सरकार ने कोविड-19 महामारी की वजह से बड़े बिक्री सौदों के लिए आशय पत्रों (ईओआई) के



लिए समय-सीमा बढ़ाई है।

हाल में सरकार ने एयर इंडिया के लिए सौंपी जाने वाली बोलियों के लिए अंतिम समय-सीमा बढ़ाकर 31 अगस्त की है। सरकार ने ईओआई सौंपने के लिए समय-

सीमा बढ़ाकर 31 जुलाई 2020 कर दी है।

दीपम सचिव ने इस बारे में सवाल का जवाब देने में बचाव किया कि क्या सरकार मौजूदा बाजार हालात को देखते हुए वित्त

विनिवेश पर एक नजर

■सरकार ने कोविड-19 की वजह से बोलियां सौंपने की समय-सीमा बढ़ा दी थी

■एलआईसी आईपीओ से सरकार को 90,000 करोड़ रुपये की रकम मिलने की संभावना है

■निवेश बैंकों का कहना है कि विपरीत बाजार हालात ने विनिवेश लक्ष्य की राह में चुनौती पैदा की है

■सरकार भारत पेट्रोलियम, एयर इंडिया में बड़ी बिक्री की योजनाओं पर काम कर रही है

वर्ष 2021 के लिए अपने विनिवेश लक्ष्य में बदलाव लाने पर विचार कर रही है।

पांडे ने बीमा दिग्गज एलआईसी की आईपीओ प्रक्रिया के बारे में ताजा जानकारी देने से

भी इनकार कर दिया।

बड़ी बिक्री में एयर इंडिया, बीईएमएल, सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स, स्कूटर्स इंडिया, भारत पंप्स एंड क्रमेशर शामिल हैं और सेल में भी कुछ हिस्सेदारी बेची जानी है।

मई में सरकार ने कहा था कि रणनीतिक क्षेत्रों में सार्वजनिक क्षेत्र की अधिकतम चार कंपनियां होंगी। भारत बॉन्ड ईटीएफ की दूसरी सीरीज के जरिये, सरकार के स्वामित्व वाली कंपनियों 14,000 करोड़ रुपये जुटा सकेंगी।

अन्य सरकारी ईटीएफ (जिनमें निवेशक अलग अलग सरकारी पीएसयू के इक्विटी शेयरों में निवेश कर सकते हैं) के विपरीत, भारत बॉन्ड ईटीएफ में निवेशकों को सरकारी पीएसयू के ऋण पत्रों के पोर्टफोलियो में निवेश की अनुमति होगी। ईटीएफ अधिदान के लिए 14 जुलाई को खुलेगा और 17 जुलाई को बंद होगा।

विकल्प से सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों को करीब 34,000 करोड़ रुपये की अनुमति मिल सकती है, और चालू वित्त वर्ष में ऐसी कई अन्य पेशकशों की संभावना है।

ईटीएफ पहली पेशकश के शुरू होने के बाद से निवेशकों के बीच लोकप्रिय हो रहा है और दो परिपक्वताओं ने सालाना आधार पर करीब 12.35 फीसदी और 12.77 फीसदी प्रतिफल दिया। पहले 100 दिन में से 84 में दो पत्रों ने बढ़त के साथ कारोबार किया। प्रत्येक परिपक्वता के लिए औसत कारोबार मात्रा लगभग 4 करोड़ रुपये रही।

फिलिप कैपिटल में निर्धारित आय खंड के कंसल्टेंट जयदीप सेन के अनुसार, मौजूदा ईटीएफ में, परिपक्वता 2023 में है जो तीन साल से कम की है, जिसने इसे दीर्घाविधि पूंजीगत लाभ कराधान या सूचकांक लाभ के अयोग्य बना दिया है। लेकिन नई परिपक्वताओं को ये लाभ मिलेंगे। सेन का कहना है कि खर्च अनुपात शून्य होने से भी ग्राहकों को इसका लाभ मिलेगा।

बिज़नेस स्टैंडर्ड



भारत बॉन्ड ईटीएफ का दूसरा चरण शुरू

पहला चरण पिछले दिसंबर में शुरू हुआ था और तब 12,400 करोड़ रुपये जुटाए गए थे

अनुप राॅय मुंबई, 3 जुलाई

एडलवाइस म्युचुअल फंड ने 3,000 करोड़ रुपये के निर्गम के लिए शुक्रवार को भारत बॉन्ड ईटीएफ का दूसरा चरण शुरू किया। इसे 11,000 करोड़ रुपये तक के आवेदन को बनाए रखने के विकल्प के साथ पेश किया गया है।

फरवरी में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने फंड प्रबंधक के तौर पर एडलवाइस और सरकार के सलाहकार के तौर पर कैपिटल के साथ दूसरे चरण को शुरू किए जाने की घोषणा की थी।

पहला चरण पिछले साल दिसंबर में शुरू किया गया था और तब 12,400 करोड़ रुपये जुटाए। 7,000 करोड़ रुपये के एनएफओ की भी 1.8 गुना का आवेदन मिले



थे। इसकी परिपक्वताएं वर्ष 2023 और 2030 से संबंधित थीं। दो नई भारत बॉन्ड ईटीएफ शृंखलाओं की परिपक्वता अप्रैल 2025 और अप्रैल 2031 होंगी। एनएफओ 14 जुलाई से शुरू और 17 जुलाई को समाप्त होगा।

एडलवाइस म्युचुअल फंड ने 2025 की परिपक्वता वाली योजना में 6,000 करोड़ रुपये के ग्रीन शू ऑफ़न के साथ 2,000 करोड़ रुपये

और 2031 की परिपक्वता में 5,000 करोड़ रुपये के ग्रीन शू ऑफ़न के साथ करीब 1,000 करोड़ रुपये जुटाने की योजना बनाई है।

ईटीएफ निपटी भारत बॉन्ड इंडेक्स की कंपनियों में निवेश करेगा जिनमें एएर रेंटिंग वाली सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां शामिल हैं। म्युचुअल फंड उन लोगों के लिए समान परिपक्वताओं के साथ फंड ऑफ फंड्स (एफओएफ) भी शुरू

करेगा, जिनके पास डीमैट खाते नहीं हैं।

एडलवाइस ने एक बयान में कहा कि इसमें 25 फीसदी हिस्सा छोटे निवेशकों के लिए और आरक्षित होगा और 75 फीसदी सेवानिवृत्त कोषों, व्यूआईबी और गैर-संस्थागत निवेशकों के लिए होगा।

ईटीएफ पर नजर रखने वाले लोगों का कहना है कि ईटीएफ

बीएसएनएल की उधारी सीमा में हुआ इजाफा

वित्त वर्ष 21 के लिए कंपनी की योजना

सुरजीत दास गुप्ता नई दिल्ली, 3 जुलाई

भारत संचार निगम को रहत मिली है क्योंकि सरकार को इस कंपनी की उधारी सीमा 31,213 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 39,713 करोड़ रुपये करने के लिए राष्ट्रपति की मंजूरी मिल गई है। इसके तहत वित्त वर्ष 2021 में कुछ शर्तों के साथ सॉवरिन गारंटी बॉन्ड के जरिए 8,500 करोड़ रुपये जुटाया जाना शामिल है। यह मंजूरी बीएसएनएल के कार्यापलट के लिए अहम है, जिसमें 4 जी नेटवर्क की स्थापना शामिल है।
इसके अलावा निजी प्रतिस्पर्धियों के साथ प्रतिस्पर्धा कर सके। इस साल फरवरी तक भारतीय मोबाइल बाजार में उसकी हिस्सेदारी सिर्फ 10.32 फीसदी थी। हालांकि यह सख्त शर्तों के साथ आया है। बीएसएनएल को वित्त वर्ष 2021 और भविष्य के लिए अपना परिचालन राजस्व सुधारने के लिए उपयुक्त कदम उठाना होगा ताकि वह आंतरिक संग्रह से पूंजीगत खर्च समेत सभी खर्च पूरी कर सके और समय पर कर्ज का पुनर्भुगतान भी कर सके।
दूसरा, उसे वित्त वर्ष 2021 के लिए अनिवार्यता का प्रमाणपत्र दूरसंचार विभाग को देना होगा कि परियोजना के क्रियान्वयन के लिए कर्ज का प्रस्ताव वित्तीय रूप से उपयुक्त है। तीसरा, उसका कुल बकाया कर्ज तय सीमा से ज्यादा नहीं होना चाहिए और उसे अपना परिचालन खर्च कम रखना होगा। साथ ही बीएसएनएल को अपनी इकायों को उचित निर्देश जारी करना होगा कि पूंजीगत व परिचालन खर्च के लिए खर्च की सही बुकिंग की गई है।
सरकारी स्वाभित्व वाली कंपनी को हाल में झटका लगा जब वह करीब 8,000 करोड़ रुपये के 4जी उपकरण की निविदा को रद्द करने के लिए बाध्य होना पड़ा। यह देसी दूरसंचार कंपनियों के विरोध में हुआ, जिसने कहा कि उनके साथ विभेद दिया गया है और यह सरकार की स्थानीय खरीद नीति के खिलाफ है। अब दूरसंचार विभाग ने तकनीकी सदस्य की अध्यक्षता में

आठ सदस्यों की समिति बनाई है, जो बीएसएनएल के विवादस्पद 4जी निविदा के लिए तकनीकी विशेषता पर सिफारिश देगी।

यहां तक कि निविदा पर नीति आयोग ने दूरसंचार विभाग और बीएसएनएल के अधिकारियों के साथ बैठक की और दूरसंचार कंपनियों टेक महिंद्रा, ट्यूलिप सॉफ्टवेयर व सी-डॉट के साथ भी। थिंक टैंक ने बीएसएनएल से कहा है कि वह अपने 4जी नेटवर्क के लिए देसी समाधान पर ध्यान दे। हालांकि बीएसएनएल के चेयरमैन पी के पुरवार ने स्पष्ट किया है कि देसी कंपनियों की प्रतिक्रिया के आधार पर यह साफ हो गया है कि उत्पादों को और विकसित करने की दरकार है। साथ ही उनकी कंपनी के पास प्रयोग के लिए रकम नहीं है, ऐसे में निविदा को अंतिम रूप देने से पहले क्षमता का प्रदर्शन होना चाहिए। अगर यह कदम उठाया गया है तो संशोधित निविदा वैश्विक विनिर्माताओं मसलन चीन की हुआवे व जेडटीई और यूरोपीय दिग्गज एरिक्सन व नोकिया के लिए मुसीबत भरा हो सकता है।

HDFC WITH YOU, RIGHT THROUGH			
हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड (सीआईएन : L70100MH1977PLC019916)			
पंजीकृत कार्यालय : रेमन हाउस, एच.टी. पारेख मार्ग, 169, बैकबे रीक्लमेशन, चर्चगेट, मुम्बई 400 020 दूरभाष : 022 6176 6000 वेबसाइट : www.hdfc.com ई-मेल : investorcare@hdfc.com			
कॉर्पोरेट कार्यालय : एचडीएफसी हाउस, एच.टी. पारेख मार्ग, 165-166, बैकबे रीक्लमेशन, चर्चगेट, मुम्बई-400 020, दूरभाष नं. : 022 6631 6000			
निवेशक सेवा विभाग : 3वीं मंजिल, रेमन हाउस, एच.टी. पारेख मार्ग, 169, बैकबे रीक्लमेशन, चर्चगेट, मुम्बई 400 020, दूरभाष नं. : 022 6141 3900			
43वीं वार्षिक आम बैठक, ई-वोटिंग तथा बुक क्लोजर की सूचना			
एतद्वारा सूचना दी जाती है कि हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड (“कॉर्पोरेशन”) के सदस्यों की 43वीं वार्षिक आम बैठक (एजीएम) कॉर्पोरेट मामले मन्त्रालय द्वारा निर्गत दिनांक 8 अप्रैल, 2020, 13 अप्रैल, 2020 तथा 5 मई, 2020 को क्रमशः सामान्य परिषद सं. 14/2020, 17/2020 तथा 20/2020 (“एमसीए परिषद”) के अनुपालन में सूचना एजीएम प्रारम्भ करने के लिए दिनांक 19 जून, 2020 में वर्णित के अनुसार प्रकाश्यों के लेन-देन हेतु द्विमागीं चौदहों कांफ्रेंस सुविधा (“वीसी”) के माध्यम से बृहस्पतिवार, 30 जुलाई, 2020 को 2:30 बजे अप. को आयोजित की जानी निर्धारित है। यदि स्थानीय प्राधिकरण अनुमति देते हैं तो भौतिक बैठक भी रामा सुन्दरी वाटुमुल ऑडिटोरियम, के.सी. कॉलेज, दिनाशा वाचा रोड, चर्चगेट, मुम्बई-400 020 पर आयोजित की जायेगी। यदि निगम भौतिक एजीएम आयोजित करने में समर्थ नहीं होता है तो इसकी सूचना सदस्यों को देने हेतु आदेश में आवश्यक सार्वजनिक सूचना निर्गत की जायेगी और ऐसी स्थिति में एजीएम में भागीदारी एमसीए परिषदों के अनुसार केवल वीसी माध्यम से ही की जायेगी।			
पुनः एमसीए परिषदों/तथा भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (‘सेबी’) द्वारा निर्गत परिषद सं. SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79 के अनुपालन में कॉर्पोरेशन ने एजीएम प्रारम्भ करने की सूचना तथा वित्त वर्ष 2019-20 की वार्षिक रिपोर्ट इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से केवल उन सदस्यों के पास भेजी है जिनके ई-मेल पते कॉर्पोरेशन या सम्बद्ध डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट (‘डी.पी.’) के पास पंजीकृत हैं। उपयुक्त दस्तावेज www.hdfc.com, www.bseindia.com तथा www.nseindia.com पर उपलब्ध हैं। एजीएम आयोजित करने की सूचना www.evoting.nsdl.com पर भी उपलब्ध है। पुनः एतद्वारा सूचना दी जाती है कि कम्पनी (प्रबन्धन एवं प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 10 के साथ पठित कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 91 एवं सेबी सूचीबद्धता एवं प्रकटन अधेश्वर) विनियम, 2015 के विनियम 42 के अनुसार सदस्यों के रजिस्टर तथा कॉर्पोरेशन की श्रेय अन्तर्गत पुस्तिक एजीएम के उद्देश्य हेतु एवं एजीएम में सदस्यों के अनुमोदन के अन्वेषीण वित्त वर्ष 2019-20 हेतु रु. 2 प्रत्येक के रु. 21 प्रति इक्विटी शेयर का लाभांश प्राप्त करने के पात्र सदस्यों का निर्धारण करने हेतु सोमवार, दिनांक 13 जुलाई, 2020 से बृहस्पतिवार, 30 जुलाई, 2020 (दोनों तिथियाँ शामिल) तक बन्द रहेगी।			
भौतिक प्रारूप में शेयर धारण करने वाले सदस्य तथा जिन्होंने सीधे खाते में लाभांश राशि की इलेक्ट्रॉनिक प्रॉविं के लिए अपने बैंक खाते का विवरण अब तक पंजीकृत/अपडेट न कराने वाले सदस्यों से निवेदन है कि वे इसे सेबी द्वारा अपेक्षित के अनुसार अपेक्षित दस्तावेज जमा करके कॉर्पोरेशन के साथ इसका पंजीकरण करा लें। इलेक्ट्रॉनिक माध्यम में शेयर धारण करने वाले सदस्यों से निवेदन है कि वे अपने बैंक खातों का विवरण अपने सम्बद्ध डीपी से पंजीकृत/अपडेट करा लें।			
पुनः एतद्वारा सूचना दी जाती है कि कथित सूचना में सूचीबद्ध सभी प्रस्तावों पर अपने मतदान के अधिकार का उपयोग करने हेतु कॉर्पोरेशन अपने सभी सदस्यों को रिमोट ई-वोटिंग की सुविधा प्रदान कर रहा है और उसने वीसी तथा ई-वोटिंग सुविधा उपलब्ध कराने के लिए नेशनल सिक्वोरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) की सेवाएँ ग्रहण की हैं। रिमोट ई-वोटिंग तथा वीसी सुविधा से सम्बन्धित कुछ महत्त्वपूर्ण विवरण निम्नलिखित हैं :			
रिमोट ई-वोटिंग तथा वीसी हेतु लिंक	www.evoting.nsdl.com		
इलेन (ई-वोटिंग इवेंट नम्बर)	112957		
रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से अथवा एजीएम के दौरान मतदान के पात्र सदस्यों के निर्धारण हेतु कट-ऑफ तिथि	बृहस्पतिवार, 23 जुलाई, 2020		
रिमोट ई-वोटिंग अवधि का प्रारम्भ	सोमवार, 27 जुलाई, 2020 को 10.00 बजे पूर्वा.		
रिमोट ई-वोटिंग के समापन की अवधि	बुधवार, 29 जुलाई, 2020 को 5.00 बजे अप.। इसके पश्चात एनएसडीएल द्वारा रिमोट ई-वोटिंग माँड्युलु निष्क्रिय कर दिया जायेगा।		
कोई व्यक्ति, जो एजीएम की सूचना भेजे जाने के पश्चात कॉर्पोरेशन का सदस्य होता है तथा कट-ऑफ तिथि तक शेयर धारण करता या जिसने कॉर्पोरेशन/डीपी के साथ अपने ई-मेल पते पंजीकृत नहीं कराये हैं, वह evoting@nsdl.co.in पर निवेदन भेजकर यूजर आईडी तथा पासवर्ड प्राप्त कर सकता है। किन्तु, यदि ऐसा सदस्य ई-वोटिंग के लिए पहले से ही एनएसडीएल के साथ पंजीकृत है तो वह मतदान हेतु अपने वर्तमान यूजर अईडी तथा पासवर्ड का प्रयोग कर सकता है। ई-वोटिंग सुविधा उन सदस्यों को जिन्होंने ई-वोटिंग के माध्यम से अपना मतदान नहीं किया है, उन्हें अपना मतदान करने हेतु एजीएम के दौरान भी ई-वोटिंग की सुविधा उपलब्ध करायी जायेगी। जिन सदस्यों ने रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से मतदान किया है वे एजीएम में शामिल तो हो सकते हैं किन्तु वे पुनः मतदान के अधिकारी नहीं होंगे। वीसी के माध्यम से बैठक में भाग लेने हेतु विस्तृत निर्देश तथा ई-वोटिंग की रीति एजीएम आयोजित करने की सूचना में प्रावधानित है।			
वीसी के माध्यम से बैठक में शामिल होने या ई-वोटिंग प्रणाली से अपना मतदान करने से सम्बन्धित किसी कठिनाई या पृष्ठताळ के मामले में सदस्य निम्नलिखित से सम्पर्क कर सकते हैं :			
हेतु	नाम	ई-मेल	सम्पर्क नम्बर
ई-वोटिंग	श्री अमित विशाल	amitv@nsdl.co.in	022-2499 4360
	सुश्री पल्लवी मात्रे	callavid@nsdl.co.in	022-2499 4545
	एवोिंगसडीएल	evoting@nsdl.co.in	1800-222-990
वीडियो कांफ्रेंस	श्री अनुभव सक्सेना	anubhavs@nsdl.co.in	022-2499 4835
कृते हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड			
ह./- अध्यक्ष			
स्थान : मुम्बई			
तिथि : 3 जुलाई, 2020			
कम्पनी सचिव			
एफसीएस : 9023			

पहली छमाही में इक्विटी फंड जुटाने की गतिविधियां बढ़ीं

सुंदर सेतुगमन और ऐश्ली कुटिनो मुंबई, 3 जुलाई

साल की पहली छमाही में इक्विटी पूंजी बाजार की गतिविधियों में 50 फीसदी की उछाल देखने को मिली, जिसकी अगुआई बड़ी कंपनियों मसलन रिलायंस इंडस्ट्रीज, हिंदुस्तान यूनिलीवर आदि के बड़े लेनदेन ने की। हालांकि इक्विटी पूंजी बाजार में शुल्क का संग्रह सात फीसदी घटा क्योंकि निवेश बैंकों ने बड़े इश्यू का कामकाज हाथ में लेने के लिए शुल्क का बलिदान दिया।

जनवरी-जून 2020 के दौरान इक्विटी पूंजी बाजार का अंडरराइटिंग शुल्क 9.6 करोड़ डॉलर रहा, जो साल 2019 की समान अवधि के मुकाबले 6.7 फीसदी कम है। वित्तीय सूचना प्रदाता रफिनटिव ने यह जानकारी दी। इक्विटी पूंजी बाजार में 52 फीसदी ज्यादा रकम जुटाई गई और यह 20 अरब डॉलर के पार निकल गई, साथ ही यह साल 2019 की पूरी अवधि के करीब-करीब बराबर है।

इक्विटी पूंजी बाजार की गतिविधियों में आर्भिक सार्वजनिक निर्गम, राइट्स इश्यू, पात्र संस्थागत नियोजन कार्यक्रम और ब्लॉक डील आदि शामिल होते हैं। बाजार के विशेषज्ञों ने कहा कि शुल्क में कमी की वजह इक्विटी पूंजी बाजार की कुल गतिविधियों में आईपीओ की कम हिस्सेदारी है। इस साल अब तक सिर्फ एसबीआई काइर्स का आईपीओ ही बाजार में उतरा है। इक्विटी पूंजी बाजार की गतिविधियों में मोटे तौर पर ब्लॉक डील के जरिए मजबूती आई।

प्राइम डेटाबेस के प्रबंध निदेशक प्रणव हल्दिया ने कहा, हमने इस साल अनुवर्ती पेशकश मसलन राइट्स इश्यू, व्यूआईपी और ब्लॉक डील की भरमार देखी है। किसी अन्य पेशकश के मुकाबले आईपीओ का शुल्क ज्यादा होता है क्योंकि पहले

POST-OFFER PUBLIC ANNOUNCEMENT FOR THE ATTENTION OF THE EQUITY SHAREHOLDERS OF UNIVERSAL PRIME ALUMINIUM LIMITED
(CIN: L28129MH1971PLC015207)
Registered Office: 771, Century Bhavan, 1st Floor, Dr Annie Besant Road, Worli, Mumbai - 400030, Maharashtra, Tel: +91 022-24304198 / 24307437,
E-mail: upalbbay@gmail.com ; investors_uppl@yahoo.com Website: www.universalprime.in Contact Person: Ms. Priyanka Motwani, (Company Secretary/ Compliance Officer)

This Post Offer Public Announcement (“Post Offer PA”) is being issued by Mr. Prakash Kumar Mohta (hereinafter referred to as the “Acquirer”) to the Public Shareholders of Universal Prime Aluminium Limited (hereinafter referred to as the “Company”) in respect of the proposed acquisition and voluntary delisting of the equity shares of face value of Rs. 10/- each (“Equity Shares”) of the Company from the BSE Limited (hereinafter referred to as the “BSE”/ “Stock Exchange”) pursuant to Regulation 18 and other applicable provisions of the Securities and Exchange Board of India (Delisting of Equity Shares) Regulations, 2009, as amended from time to time (“Delisting Regulations”) (“Delisting Offer”). This Post Offer PA should be read in conjunction with the Public Announcement dated November 27, 2019 (“Public Announcement”/ “PA”) and the Letter of Offer (“LOF”) dated November 27, 2019. The capitalized terms used but not defined in this Post Offer PA shall have the same meaning assigned to them in the PA and the LOF.

The Acquirer had issued the PA seeking to acquire, in accordance with the Delisting Regulations and on the terms and conditions set out therein and in the LOF 41, 43,665 Equity Shares representing 52.01% of paid-up equity share capital of the Company from its Public Shareholders. The Public Shareholders holding Equity Shares were invited to submit consent letter and transfer of shares to Acquirer, in accordance with the Delisting Regulations.

1. Discovered Price and Exit Price

The Acquirer proposes to acquire the entire equity shares of the Company from the Public Shareholders indicating an exit price of Rs. 3.50/- per Equity Share specifically dispensing with the exit price discovery through book building method in terms of Regulation 27 (4) under chapter VII of SEBI (Delisting of Equity Shares) Regulations, 2009. The Exit Price is justified with particular reference to the applicable parameters mentioned in Regulation 15 SEBI (Delisting of Equity Shares) Regulations, 2009 and specifically the consent for dispensing with the exit price discovery through book building method has been communicated to the public shareholders.

2. Success of the Delisting Offer

- In terms of Regulation 27 (3)(d) under chapter VII of the Delisting Regulations, and as stated in clause 8.1 of the LOF, the Delisting Offer will be deemed to be successful only if a minimum of 37,29,299 Equity Shares (90% of the public shareholding) give their consent in writing to the proposal for delisting, and have consented either to sell their equity shares at the price offered by the Acquirer/promoter or to remain holders of the equity shares even if they are delisted.
 - The acquirer has received consent for delisting for 3822095 shares i.e. equal to 92.24% of the public holding which is more than required for delisting offer to be successful. The acquirer shall acquire 593759 shares which were validly tendered at the exit price. The balance 3228336 equity share representing 40.52% of total paid-up capital of the Company held by various shareholders have agreed to continue as shareholder of the Company and they may also be considered as Promoter of the Company. After completion of such acquisition the shareholding the promoters shall be shall be 95.964% of the paid up equity share capital of the Company.
 - In terms of Delisting Regulations, and as per Regulation 27 (3) (c) the Public Shareholders holding Equity Shares were required to give their consent in writing for the Delisting offer, provided that if the Acquirer along with the Share Transfer Agent to the Offer demonstrate that he has delivered the LOF of this Delisting Offer to all the Public Shareholders either through registered post or speed post or courier or hand delivery with proof of dispatch or through email as a text or as an attachment to the email or as a notification providing electronic link or uniform resource locator including a read receipt (referred to as the “LOF Delivery Requirement”). Further, pursuant to Explanation I of Regulation 17 (1)(b) 27 (3) (c) of the Delisting Regulations the LOF Delivery Requirement is deemed to have been complied with (i) if the Acquirer or the Share Transfer Agent to the Offer dispatches the Letter of Offer to all the Public Shareholders of the Company by registered post or speed post through the India Post and is able to provide a detailed account regarding the status of delivery of the Letter of Offer (whether delivered or not) sent through India Post; (ii) if the Acquirer or the Share Transfer Agent to the Offer is unable to deliver the Letter of Offer to certain Public Shareholders of the Company by modes other than speed post or registered post of India Post, efforts should have been made to dispatch the Letter of Offer to them by speed post or registered post of India Post and is able to provide a detailed account regarding the status of delivery of the Letter of Offer (whether delivered or not) sent through India Post.
 - Mareshwari Datamatics Private Limited., Registrar to the Offer has dispatched the Letter of Offer on 29th November, 2019 to all the Public Shareholders as on the Specified Date i.e., November 27, 2019 through Registered Post/ Speed Post/ Email (where email ids were available). The Registrar has confirmed that the LOF has been dispatched to all the Public Shareholders by Registered Post/Speed Post/ Email (where email ids were available) and the Acquirer is able to provide a detailed account regarding the status of delivery of LOF.
 - The Delisting Offer is thus deemed to be successful in terms of the Delisting Regulations
- All the Public Shareholders who have validly tendered their Equity Shares at the Exit Price will be paid consideration at the Exit Price of Rs. 3.50/- (Rupees Three Fifty Paish Only). The last date of payment of consideration to all the Public Shareholders who have validly tendered their Equity Shares at the Exit Price originally scheduled on or before Wednesday, April 15, 2020, which the Acquirer could not complete as there was country wide lock down & Acquirer could access their office only after 8th June, 2020.
- Subsequently, the Company will initiate the necessary steps to delist the Equity Shares of the Company from the BSE. The date of delisting of Equity Shares shall be announced in the same newspapers in which the PA and this Post Offer PA has appeared.
- Outstanding Equity Shares after Delisting

In accordance with Regulation 21 of the Delisting Regulations, all Public Shareholders who did not participate or were not able to participate or who unsuccessfully tendered their Equity Shares will be able to offer their Equity shares to the to the Promoter/Acquirer at the Exit Price Rs. 3.50/- per equity share for the period of one year starting from the date of delisting of the Equity Shares from the BSE LT (“Date of Delisting”) i.e. (“Exit Period”). In the events of any public shareholder not receiving, or misplacing their Exit offer Letter, they may obtain a copy by writing to the Company or the Registrar and share transfer agent of the Company.
- All other terms and conditions set forth in the PA and LOF remain unchanged.
- This Post Offer PA is issued by the Acquirer in terms of Regulation 18 of the Delisting Regulations. If the Public Shareholders have any query with regard to the Delisting Offer, they may contact the Company or the Registrar to the Offer.

REGISTRAR TO THE DELISTING OFFER
Mareshwari Datamatics Private Limited
CIN: U20221WB1982PTC034886
23, R. N. Mukherjee Road 5th Floor, Kolkata-700 001 **Tel. No.**: +91 33 2248 2248 **E-Mail ID:** mdpdc@yahoo.com
Contact Person: Mr. S. Rajgopal **Website:** www.mdpl.in **SEBI Reg. No.:** INR000000353

Note: The Acquirer could not make the newspaper advertisement on 27th March, 2020 in terms of Regulation 18 and other applicable provisions of the Securities and Exchange Board of India (Delisting of Equity Shares) Regulations, 2009, as amended from time to time (“Delisting Regulations”) (“Delisting Offer”) as there was Country wide lock-down due to impact of CoVID –19 pandemic from 22nd March, 2020, the Acquirer could not access their office till 08th June, 2020. Hence various events to be taken by the Acquirer/Promoter got delayed, which was major force, i.e. reason beyond the control of Acquirer/Promoter as the entire country was in lock down mode, there were restrictions on the physical movement of every individual in the country.

Place: Kolkata

Date: 03-07-2020

For and Behalf of the Acquirer

S/-

Prakash Kumar Mohta

Start-ups try to woo talent back to India

SAI ISHWAR
Mumbai, 3 July

With the uncertain business environment triggered by the coronavirus (Covid-19) pandemic and immigration-related issues, many talented Indians in the US are being forced to return. Start-ups and software companies are seeing this as an opportunity to enrich their talent base.

According to industry experts, a stricter visa regime and closure of onshore opportunities in the US are likely to result in a reverse brain drain.

Indian start-ups and software product companies are trying to attract engineers and programmers who are either stranded in India because of the lockdown or HIB visa holders who have been laid off. They are also setting sights on those who are contemplating moving back home due to uncertainties around the visa processing, say HR firms and industry experts.

"Product-based start-ups that have funds are luring mid-level workers having skills in front-end architect solutions and product development. The global exposure of such candi-

HEMCOMING



■ Indian start-ups are scouting for employees in front-end architect solutions and product development; Zomato and Ixigo are tapping the opportunity

■ The talent is a great fit to fill vacancies on contract and consultant roles, especially in digital and cloud projects, say HR experts

■ Last week, Trump signed a proclamation to restrict HIB and other non-immigration visas until the end of 2020; the federal rules require a visa holder, family to leave the US within 60 days of losing their job

dates is an added advantage," said Aditya Narayan Mishra, chief executive officer (CEO) of CIEL HR Services.

Last Monday, US President Donald Trump signed a proclamation to restrict HIB and other non-immigration visas until the end of 2020. Around 1,500 visa holders, who visited India before the lockdown for medical emergencies and vacations, are also in limbo because of the executive order.

Also, the current federal rules require an HIB visa holder

er to leave the US along with family members within 60 days of losing their jobs. Those on HIB visas are not eligible for unemployment and social security benefits.

"Visa holders stuck in India, too, have been furloughed or given an option to temporarily work in offshore locations in Hyderabad or Bengaluru or transferred to other projects without the employee's consent. So, these employees are exploring local opportunities," he added.

Mukesh Ambani unveils JioMeet to take on Zoom

Zoom, one of the few success stories of the Covid-19 pandemic, now faces a new competitor in an app backed by Asia's wealthiest person Mukesh Ambani. Ambani's Reliance Industries, which has scored billions of dollars of investments from Facebook to Intel for its digital businesses, launched the JioMeet video conferencing app after beta testing. The app has already garnered more than 100,000 downloads on the Google Play Store after becoming available Thursday evening.

Like Google Meet, Microsoft Teams and other services, JioMeet offers unlimited high-definition calls — but unlike Zoom, it doesn't impose a 40-minute time limit. Calls can go on as long as 24 hours, and all meetings are encrypted and password-protected. The launch coincided with a nationwide ban on dozens of popular apps from Chinese technology giants.

The app is one facet of Ambani's rapidly expanding digital empire, which includes India's largest telecom operator with nearly 400 million users. "JioMeet will be a very



JioMeet is just one facet of Mukesh Ambani's rapidly expanding digital empire

credible disruptor in the space," said Utkarsh Sinha, managing director of boutique consultancy Bexley Advisors. "Just the fact that it has no time limits on calls makes it a serious challenger to Zoom, despite its entrenchment."

Jio Platforms is amassing a wide range of services from music streaming to online retail and payments, fast turning into an e-commerce juggernaut that can take on Google and Amazon on its own home turf.

JioMeet is also debuting at a time Zoom users have accused the service of security flaws.

BLOOMBERG

THE GREAT EASTERN SHIPPING CO. LTD.
CIN: L35110MH1948PLC006472
Registered Office: Ocean House, 13/A, Dr. Annie Besant Road, Worli, Mumbai - 400018.
Tel No.: +91 (22) 6661300/24922100; Fax: +91 (22) 24925900
Email: shares@greatship.com; Website: www.greatship.com

NOTICE IS HEREBY GIVEN that the 72nd Annual General Meeting of the members of The Great Eastern Shipping Co. Ltd. will be held through Video Conferencing ("VC") / Other Audio Visual Means ("OAVM") on Thursday, July 30, 2020 at 3.00 p.m. in compliance with the applicable provisions of the Companies Act, 2013 and the General Circular No. 20/2020 dated May 05, 2020 issued by the Ministry of Corporate Affairs.

The Notice of the AGM and the Annual Report for FY 2019-20 will be sent to the members of the Company whose email addresses are registered with the Company/Depository Participant(s) by way of email. The same will also be available at the Company's website: www.greatship.com and on the websites of BSE Limited: www.bseindia.com and National Stock Exchange of India Limited: www.nseindia.com.

Members will be able to attend the AGM through VC/OAVM at <http://emeetings.kfintech.com>. All the business as set out in the Notice of AGM will be transacted through voting by electronic means. Members may cast their votes through remote e-voting at <https://evoting.karvy.com>. The facility for e-voting will also be available during the AGM ("Insta Poll") and members attending the AGM who have not cast their vote(s) by remote e-voting will be able to vote at the AGM through Insta Poll.

Detailed instructions (including User ID and Password) for attending the AGM and e-voting (including remote e-voting) will be sent to the Members through email.

If the member is already registered with e-voting platform of the Company's Registrar & Share Transfer Agent, KFin Technologies Private Limited ('Kfin'), he/she can use his/her existing User ID and Password for login.

The procedure of registering/updating email addresses is as follows:

- Members holding shares in physical mode are requested to register / update their email addresses by writing to the Company with details of folio number and attaching a self-attested copy of PAN card at shares@greatship.com or to KFin at einward.ris@kfintech.com
- Members holding shares in dematerialised mode are requested to register / update their email addresses with the Depository Participant(s) with whom they maintain their demat accounts.

The members may also register / update their bank account details for receiving dividend as may be declared by the Company from time to time by writing a letter or by completing the application requesting payment of dividend through ECS (available on the website of the Company). Scanned copy of the letter / application duly filled in (along with self-attested copies of your PAN and AADHAR Card and cancelled cheque leaf-first two pages of bank passbook) may be emailed to the Company at shares@greatship.com or to Kfin at einward.ris@kfintech.com

The original documents as aforesaid may be sent in due course to the Company at its registered office or to the RTA at the following address:

KFin Technologies Private Ltd.
Unit: The Great Eastern Shipping Co. Ltd.
Selenium Tower B, Plot No. 31 & 32, Gachibowli, Financial District,
Nanakramguda, Hyderabad-500032

For The Great Eastern Shipping Company Limited

Place : Mumbai Jayesh M. Trivedi
Date : 03.07.2020 President (Secl. & Legal) & Company Secretary

APPOINTMENTS

देवगिरी नागरी सहकारी बँक लि. औरंगाबाद
मुख्य कार्यालय : अर्थ कॉन्सेप्ट, केसलसिंगपुर, अहमदनगर, औरंगाबाद.
दूरध्वनी क्र. (०२४०) २३३४२२१, २४०२०००, मोबाईल : ७०२८९९९९९९
ई-मेल : hr@deoginibank.com, Website : www.deoginibank.com

आधुनिक संगणक प्रणालीने सज्ज, संपूर्ण महाराष्ट्रात ३९ शाखांचा विस्तार असलेल्या बँकेत वरिष्ठ उप मुख्य अधिकारी (Senior Deputy Executive Officer), आगि वरिष्ठ अधिकारी (Data Center) पदाच्या जागा भरावयाच्या आहेत, त्यासाठी बँकेची जबाबदारी व आव्हाने स्विकारण्याची मानसिकता असणाऱ्या अनुभवी अधिकाऱ्यांकून अर्ज मागविण्या जात आहेत.

१) वरिष्ठ उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी ०२ पद

- शैक्षणिक पात्रता : पदवीधर व CAIIB किंवा चार्टर्ड अकाउंटंट/कॉस्ट अकाउंटंट किंवा पदव्युत्तर पदवी
- वयोमर्यादा : ३५ ते ५५ वर्ष (शिथिलरुम)
- अनुभव : बँकेत शाखाधिकारी पदापेक्षा वरिष्ठ पदाचा किंवा वरिष्ठ अधिकारी पदाचा किमान १० वर्षांचा अनुभव असावा.

२) वरिष्ठ अधिकारी (डेटा सेंटर) ०१ पद

- किमान शैक्षणिक : बी.ई. (कॉम्प्युटर/आयटी)/तत्सम शैक्षणिक पदवी/पदव्युत्तर पदवी, Knowledge of C++/Java Programming, Oracle.
- वयोमर्यादा : ३५ ते ५५ वर्ष (शिथिलरुम)
- अनुभव : आय.टी. मधील किमान ०५ वर्षांचा मध्यमव उच्च अधिकारी पदाचा अनुभव, बँकेची क्षेत्रातील डेटा सेंटरचा अनुभव असणाऱ्या उमेदवारास प्राधान्य दिले जाईल.

* उपरोक्त पदांसाठी बँकेतील अनुभव स्वागतार्ह.

वरील उल्लेखलेल्या पात्रता धारण करणाऱ्यांनी आपले अर्ज पुढील १५ दिवसांचे आत, खालील प्रमाणे पाठवावेत.
- जाहिरातीत नमुद बँकेच्या संकेतस्थळावर नमुना अर्ज उपलब्ध आहे.
- नमुना अर्जासोबत आपली माहिती भरून सदर अर्ज आपल्या उध्यायवत बायोडाटासह कुरिअर/पोस्ट/मेल या माध्यमाद्वारे पाठवावेत.
मुख्य कार्यकारी अधिकारी

चालको NALCO
(A Government of India Enterprise)
Bhubaneswar-751013, Odisha, India
CIN : L27203OR1981GOI000920

OPEN TENDER NOTICE

No.NBC/M/01/GT/PCP/2020 Date : 10/06/2020
Online bids in CPP Portal are invited for supply of the following materials for our Smelter Plant, Angul (Odisha), India from bonafide Indigenous manufactures / suppliers or their accredited agents. Item Description : Calcined PetroleumCoke, Tender Quantity, (MT) : 64,150 MT - 84,150 MT +/- 5% at NALCO's Option. Last date of tender Submission : 08/07/2020 Up to 13:00 Hrs (IST). Tender documents and online submission procedure can be downloaded from Nalco's Website i.e www.nalcoindia.com and www.eprocure.gov.in. Please refer to the website for any further updation or modification in NIT.

GM (MATERIALS)

Mahindra FINANCE
MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL SERVICES LIMITED
Registered Office: Gateway Building, Apollo Bunder, Mumbai - 400 001.
CIN: L65921MH1991PLC059642
Tel: +91 22 6652 6000 | Fax: +91 22 2498 4170
Website: www.mahindrafinance.com | Email: investorhelpline_mmfsl@mahindra.com

NOTICE

Notice is hereby given in compliance with Regulation 29 read with Regulation 47 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, that a Meeting of the Board of Directors of the Company will be held on Saturday, 18th July, 2020 to interalia, consider and approve the Unaudited Standalone and Consolidated Financial Results of the Company for the first quarter ended 30th June, 2020, subject to a limited review by the Statutory Auditors of the Company.

This intimation is also available on the website of BSE Limited (www.bseindia.com) and National Stock Exchange of India Limited (www.nseindia.com) where the Company's shares are listed and may also be accessed on the website of the Company at <http://www.mahindrafinance.com>.

For Mahindra & Mahindra Financial Services Limited

Place : Mumbai Arnava M. Pardhiwalla
Date : 3rd July, 2020 Company Secretary & Compliance Officer

SOLARA
Active Pharma Sciences
SOLARA ACTIVE PHARMA SCIENCES LIMITED
CIN: L24230MH2017PLC291636
Registered Office: 201, Devavarta, Sector 17, Vashi, Navi Mumbai, 400 703, Tel: +91 22 27892942; Fax: +91 22 27892942
Corporate Office: 'Batra Centre', No. 28, Sardar Patel Road, Guindy, Chennai 600 032
Tel: + 91 44 43446700, 22207500; Fax: +91 44 22350278, Email: investors@solara.co.in; Website: www.solara.co.in

ANNUAL GENERAL MEETING TO BE HELD THROUGH VIDEO CONFERENCE, RECORD DATE AND DIVIDEND INFORMATION

- Shareholders may note that the 3rd Annual General Meeting (AGM) of the Company will be held over video conference on Tuesday, August 4, 2020 at 10.30 AM in compliance with General Circular numbers 20/2020, 14/2020, 17/2020 and all other applicable laws and circulars issued by the Ministry of Corporate Affairs (MCA), Government of India and Securities and Exchange Board of India (SEBI), to transact the business that will be set forth in the Notice of the Meeting.
- In compliance with the above circulars, electronic copies of the Notice of the AGM and Annual Report for Financial Year 2019-20 will be sent to all the shareholders whose email addresses are registered with the Company/ Depository Participant(s). Shareholders holding shares in dematerialized mode are requested to register their email addresses and mobile numbers with their relevant depositories through their depository participants. Shareholders holding shares in physical mode are requested to register their email addresses and mobile numbers with the Company's Registrar and Share Transfer Agent Cameo Corporate Services Limited at <https://investors.cameoindia.com>. The notice of the AGM and Annual Report for fiscal 2020 will also be made available on the Company's website, at www.solara.co.in and stock exchange websites.
- Further the registrar of Members shall be closed from July 30, 2020 to August 4, 2020 (both days inclusive) ("Book closure dates") for the purpose of ascertaining the eligible shareholders for participating in the AGM and for the payment of Dividend for the Financial Year 2019-20, if approved at the AGM.
- Shareholders will have an opportunity to cast their vote remotely on the business as set forth in the Notice of the AGM through electronic voting system. The manner of voting remotely for shareholders holding shares in dematerialized mode, physical mode and for shareholders who have not registered their email addresses will be provided in the Notice to the shareholders. In this regard, Members whose email ids for all communications and/or bank account details for receipt of Dividend amount directly to the bank accounts, are not registered with their Depository Participants are hereby requested to register / update their email ids and Bank Account details with the respective Depository Participants or with Company's Registrar and Share Transfer Agent Cameo Corporate Services Limited by following the below instructions:

The shareholders holding shares in physical form, shall register their e-mail id and mobile no. online in <https://investors.cameoindia.com>. For registering the Bank account details, the shareholders shall forward the following details to investor@cameoindia.com.

- Folio No
- Name of the Shareholder
- Scan copy of the share certificate (for Physical Shareholder)
- Self-attested scan copy of PAN card and
- Self-attested scan copy of Aadhar card
- Name and Branch of Bank
- Bank Account Type
- Bank Account Number
- MIRAC Code
- IFSC Code and
- Scanned copy of the cancelled cheque with the name of the shareholder printed.

For the shareholder holding shares in demat form, the details of e-mail, mobile no. and the Bank account details shall be updated with their respective DPs.

- The Company is providing the remote e-voting facility as well as e-voting facility during the meeting. The member who have not registered their e-mail id with RTA and or Depository Participants can also cast their vote through remote e-voting system or e-voting during the meeting and the detailed procedure for remote e-voting and e-voting shall be given in the AGM Notice.
- Shareholders may note that the Income Tax Act, 1961 (Act), as amended by the Finance Act, 2020, mandates that dividends paid or distributed by a Company after April 1, 2020 shall be taxable in the hands of shareholders. The Company shall therefore be required to deduct tax at source (TDS) at the time of making the payment of dividend. In order to enable us to determine the appropriate TDS rate as applicable, shareholders are requested to submit the following documents in accordance with the provisions of the Act.

For Resident Shareholders, taxes shall be deducted at source under Section 194 of the Act, as follows

Shareholders having valid PAN	7.5% or as notified by the Government of India
Shareholders not having PAN / valid PAN	20% or as notified by the Government of India

However, no tax shall be deducted on the dividend payable to a resident individual shareholder if the total dividend to be received by them during Financial Year 2020-21 does not exceed Rs. 5,000 and also in cases where shareholders provide Form 15G / Form 15H (applicable to an individual's age of 60 years or more) subject to conditions specified in the Act. Resident shareholders may also submit any other document as prescribed under the Act to claim a lower/nil withholding tax. PAN is mandatory for shareholders providing Form 15G/15H or any other document as mentioned above.

For Non-resident Shareholders, taxes are required to be withheld in accordance with the provisions of Section 195 and other applicable sections of the Act, at the rates in force. The withholding tax shall be at the rate of 20% (plus applicable surcharge and cess) or as notified by Government of India on the amount of dividend payable. However, as per Section 90 of the Act, non-resident shareholders have the option to be governed by the provisions of the Double Tax Avoidance Agreement (DTAA) between India and the country of tax residence of the shareholder, if they are more beneficial to them. For this purpose, i.e. to avail the benefits under the DTAA, non-resident shareholders will have to provide the following by sending a request to Company's RTA Ms. Cameo Corporate Services Limited on the email address - Investor@cameoindia.com on or before July 23, 2020:

- Self-declaration by the shareholder of having no Permanent Establishment in India in accordance with the applicable Tax Treaty.
- Self-declaration of Beneficial ownership by the shareholder
- Copy of Tax Residence Certificate (TRC) for FY 2020-21 obtained from the revenue authorities of the country of tax residence, duly attested by shareholder.
- Copy of the PAN Card allotted by the Indian Income Tax authorities duly attested by the shareholder.
- Self-declaration in Form 10 F.
- Any other documents as prescribed under the Act for withholding of taxes if applicable, duly attested by the shareholder.

Place : Chennai
Date : July 2, 2020
For Solara Active Pharma Sciences limited
S Murali Krishna
Company Secretary

MONARCH NETWORK CAPITAL LIMITED
CIN:L65920MH1993PLC075393
Regd. Off: Office No. 901/902, Atlanta Centre,
Opp. Udyog Bhavan, Sonawala Road, Goregaon (East),
Mumbai- 400063. Tel: +91-22-3064 1600, Fax: +91-22-2685 0257,
Email: cs@mncggroup.com | Website: www.mncggroup.com

NOTICE OF POSTAL BALLOT

Notice is hereby given that pursuant to provisions of Section 110 and other applicable provisions of the Companies Act, 2013 read with Rule 22 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 and such other applicable laws, rules and regulations (including any statutory modifications or re-enactments thereof, for the time being in force) and as per Regulations 44 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 to seek approval of shareholders through Postal Ballot (E voting) for the below Special Business:

- Reclassification of shares of certain promoters from Promoter To Public Category.

Further in terms of the MCA Circulars, in view of the current extraordinary circumstances due to COVID-19 pandemic requiring social distancing, companies are advised to take all decisions requiring members' approval, other than items of ordinary business or business where any person has a right to be heard, through the mechanism of postal ballot / e-voting in accordance with the provisions of the Companies Act and rules made thereunder, without holding a general meeting that requires physical presence of members at a common venue. The MCA has clarified that for companies that are required to provide e-voting facility under the Companies Act, while they are transacting any business(es) only by postal ballot up to September 30, 2020, or till further orders, whichever is earlier, the requirements provided in Rule 20 of the Rules as well as the framework provided in the MCA Circulars will be applicable mutatis mutandis. Further, the Company will send Postal Ballot Notice only by email to all its shareholders who have registered their email addresses with the Company or depository / depository participants and the communication of assent / dissent of the members will take place through the remote e-voting system. This Postal Ballot is accordingly being initiated in compliance with the MCA Circulars.

In compliance with the requirements of the MCA Circulars thus hard copy of Postal Ballot Notice along with Postal Ballot Forms and pre-paid business envelope will not be sent to the shareholders for this Postal Ballot.

Members are further informed that the Company has sent Notice of Postal Ballot at the registered e-mail ids on Friday, 03rd July, 2020 to the shareholders whose names appear in the Register of Members as on Friday, 26th June, 2020 being cut off date. Further shareholders whose email ids are not registered, may temporarily get their email id registered with the Company's Registrar and Share Transfer Agent, Skyline Financial Services Private Limited, by clicking the link <http://www.skylinert.com> (Email Reg. pph), and by following the registration process as guided. Post successful registration of the email, the shareholder would get soft copy of the notice and the procedure for e-voting along with the User ID and Password to enable e-voting for this Postal Ballot. In case of any queries, shareholder may write to info@skylinert.com.

The Postal Ballot Notice and instructions for e-voting may also be accessed on the website of the company i.e. www.mncggroup.com, at www.bseindia.com and www.evoting.nsdl.com

The Company is providing facility of voting through electronic mode (E voting) through NSDL e-voting Platform. The e-voting shall commence from Monday, 06th July, 2020 (09.00 A.M.) till Tuesday, 04th August, 2020 (05.00 P.M.). The e-voting facility shall be disabled by NSDL thereafter. The voting rights of members shall be in proportion to their shares of the paid up equity share capital of the Company as on the cut-off date i.e. Friday, 26th June, 2020.

Further the Board of Directors of the Company have appointed M/s. VKM & Associates, Company Secretaries, Mumbai as Scrutinizer for conducting the voting process through Postal Ballot (e-voting) in accordance with the law and in a fair and transparent manner.

The Scrutinizer will submit his Report to the Chairman of the Company, upon completion of scrutiny of Postal Ballot (e-voting) provided by NSDL in a fair and transparent manner. The result of the Postal Ballot will be declared on Wednesday, 05th August, 2020 and will be communicated to the BSE Limited and further will be posted on the Company's website www.mncggroup.com.

For any grievances connected with the electronic voting, you may refer the Frequently Asked Questions (FAQs) for Shareholders and e-voting user manual for Shareholders available at the download section of www.evoting.nsdl.com or call on toll free no.: 1800-222-9900 or send a request at evoting@nsdl.com or the undersigned at the contact details mentioned above.

For Monarch Network Capital Limited
Sd/-
Rupali Verma
Place: Mumbai
Date: 04th July, 2020
Company Secretary & Compliance Officer

POST-OFFER PUBLIC ANNOUNCEMENT FOR THE ATTENTION OF THE EQUITY SHAREHOLDERS OF UNIVERSAL PRIME ALUMINIUM LIMITED

(CIN: L28129MH1971PLC015207)
Registered Office: 771, Century Bhavan, 1st Floor, Dr Annie Besant Road, Worli, Mumbai - 400030, Maharashtra, Tel: +91 022-24304198 / 24307437,
E-mail: upalbby@gmail.com; investors_uppl@yahoo.com Website: www.universalprime.in
Contact Person: Ms. Priyanka Motwani, (Company Secretary/ Compliance Officer)

This Post Offer Public Announcement ("Post Offer PA") is being issued by Mr. Prakash Kumar Mohta (hereinafter referred to as the "Acquirer") to the Public Shareholders of Universal Prime Aluminium Limited (hereinafter referred to as the "Company") in respect of the proposed acquisition and voluntary delisting of the equity shares of face value of Rs. 10/- each ("Equity Shares") of the Company from the BSE Limited (hereinafter referred to as the "BSE"/ "Stock Exchange") pursuant to Regulation 18 and other applicable provisions of the Securities and Exchange Board of India (Delisting of Equity Shares) Regulations, 2009, as amended from time to time ("Delisting Regulations") ("Delisting Offer"). This Post Offer PA should be read in conjunction with the Public Announcement dated November 27, 2019 ("Public Announcement"/ "PA") and the Letter of Offer ("LOF") dated November 27, 2019. The capitalized terms used but not defined in this Post Offer PA shall have the same meaning assigned to them in the PA and the LOF.

The Acquirer had issued the PA seeking to acquire, in accordance with the Delisting Regulations and on the terms and conditions set out therein and in the LOF 41, 43,665 Equity Shares representing 52.01% of paid-up equity share capital of the Company from its Public Shareholders. The Public Shareholders holding Equity Shares were invited to submit consent letter and transfer of shares to Acquirer, in accordance with the Delisting Regulations.

1. Discovered Price and Exit Price

The Acquirer proposes to acquire the entire equity shares of the Company from the Public Shareholders indicating an exit price of Rs. 3.50/- per Equity Share specifically dispensing with the exit price discovery through book building method in terms of Regulation 27 (4) under chapter VII of SEBI (Delisting of Equity Shares) Regulations, 2009. The Exit Price is justified with particular reference to the applicable parameters mentioned in Regulation 15 SEBI (Delisting of Equity Shares) Regulations, 2009 and specifically the consent for dispensing with the exit price discovery through book building method has been communicated to the public shareholders.

2. Success of the Delisting Offer

- In terms of Regulation 27 (3)(d) under chapter VII of the Delisting Regulations, and as stated in clause 8.1 of the LOF, the Delisting Offer will be deemed to be successful only if a minimum of 37,29,299 Equity Shares (90% of the public shareholding) give their consent in writing to the proposal for delisting, and have consented either to sell their equity shares at the price offered by the Acquirer/promoter or to remain holders of the equity shares even if they are delisted.
- The acquirer has received consent for delisting for 3822095 shares i.e. equal to 92.24% of the public holding which is more than required for delisting offer to be successful. The acquirer shall acquire 593759 shares which were validly tendered at the exit price. The balance 328336 equity share representing 40.52% of total paid-up capital of the Company held by various shareholders have agreed to continue as shareholder of the Company and they may also be considered as Promoter of the Company. After completion of such acquisition the shareholding of the promoters shall be 95.964% of the paid up equity share capital of the Company.
- In terms of Delisting Regulations, and as per Regulation 27 (3) (c) the Public Shareholders holding Equity Shares were required to give their consent in writing for the Delisting Offer, provided that if the Acquirer along with the Share Transfer Agent to the Offer demonstrate that he has delivered the LOF of this Delisting Offer to all the Public Shareholders either through registered post or speed post or courier or hand delivery with proof of dispatch or through email as a text or as an attachment to the email or as a notification providing electronic link or uniform resource locator including a read receipt (referred to as the "LOF Delivery Requirement"). Further, pursuant to Explanation I of Regulation 17(1)(b) 27 (3) (c) of the Delisting Regulations the LOF Delivery Requirement is deemed to have been complied with (i) if the Acquirer or the Share Transfer Agent to the Offer dispatches the Letter of Offer to all the Public Shareholders of the Company by registered post or speed post through the India Post and is able to provide a detailed account regarding the status of delivery of the Letter of Offer (whether delivered or not) sent through India Post; (ii) if the Acquirer or the Share Transfer Agent to the Offer is unable to deliver the Letter of Offer to certain Public Shareholders of the Company by modes other than speed post or registered post of India Post, efforts should have been made to dispatch the Letter of Offer to them by speed post or registered post of India Post and is able to provide a detailed account regarding the status of delivery of the Letter of Offer (whether delivered or not) sent through India Post.
- Maheshwari Datamatics Private Limited, Registrar to the Offer has dispatched the Letter of Offer on 29th November, 2019 to all the Public Shareholders as on the Specified Date i.e., November 27, 2019 through Registered Post/ Speed Post/ Email (where email ids were available). The Registrar has confirmed that the LOF has been dispatched to all the Public Shareholders by Registered Post/Speed Post / Email (where email ids were available) and the Acquirer is able to provide a detailed account regarding the status of delivery of LOF.
- The Delisting Offer is thus deemed to be successful in terms of the Delisting Regulations

All the Public Shareholders who have validly tendered their Equity Shares at the Exit Price will be paid consideration at the Exit Price of Rs. 3.50/- (Rupees Three Fifty Paise Only). The last date of payment of consideration to all the Public Shareholders who have validly tendered their Equity Shares at the Exit Price originally scheduled on or before Wednesday, April 15, 2020, which the Acquirer could not complete as there was country wide lock down & Acquirer could access their office only after 8th June, 2020.

Subsequently, the Company will initiate the necessary steps to delist the Equity Shares of the Company from the BSE. The date of delisting of Equity Shares shall be announced in the same newspapers in which the PA and this Post Offer PA has appeared.

Outstanding Equity Shares after Delisting

In accordance with Regulation 21 of the Delisting Regulations, all Public Shareholders who did not participate or were not able to participate or who unsuccessfully tendered their Equity Shares will be able to offer their Equity shares to the Promoter Acquirer at the Exit Price Rs. 3.50/- per equity share for the period of one year starting from the date of delisting of the Equity Shares from the BSE Ltd. ("Date of Delisting") i.e. ("Exit Period"). In the events of any public shareholder not receiving, or misplacing their Exit Offer Letter, they may obtain a copy by writing to the Company or the Registrar and share transfer agent of the Company.

